



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

தக்ஷிண் பாரதத் ராஷ்ட்ரமத் | தினகரி ஹிந்தி நாளிதழ் | चेन्नई और बैंगलूर से एक साथ प्रकाशित



5 उत्तर प्रदेश रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है : राजनाथ सिंह

6 जांच के घेरे में राजनीति, राजनीति के घेरे में जांच

7 फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ भी जरूरी : अदा शर्मा

फर्स्ट टेक

डीआरडीओ ने 'स्कैमजेट' इंजन का लंबी अवधि का जमीनी परीक्षण किया

नई दिल्ली/भाषा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) ने 'स्कैमजेट कंबर्स्टर' का लंबी अवधि का सफल जमीनी परीक्षण करके हाइपरसोनिक मिसाइलों के विकास क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने स्कैमजेट-संचालित हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी पर अद्यतन जानकारी साझा करते हुए कहा कि हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल) ने इस तरह की मिसाइलों के विकास के क्षेत्र में एक "अभूतपूर्व उपलब्धि" हासिल की है। इसने एक बयान में कहा कि डीआरडीएल ने 9 जनवरी को अपने अत्याधुनिक 'स्कैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट' (एससीपीटी) प्रतिष्ठान में 'स्कैमजेट कंबर्स्टर' का लंबी अवधि का जमीनी परीक्षण सफलतापूर्वक किया।

रूस ने यूक्रेन के खिलाफ 'ओरेथ्रिक' बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया

कीव/एपी। रूस ने शुक्रवार को कहा कि उसने यूक्रेन पर भीषण हमले में अन्य हथियारों के साथ नई 'ओरेथ्रिक' बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूसी हमले में राजधानी कीव में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। रूस ने यह नहीं बताया कि 'ओरेथ्रिक' ने कहा हमला किया। लेकिन रूसी मीडिया और सैन्य ब्लॉगर्स ने कहा कि इसने यूक्रेन के पश्चिमी ल्यूव क्षेत्र में एक विशाल भूमिगत प्राकृतिक गैस भंडारण को निशाना बनाया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह हमला पिछले महीने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर कथित तौर पर यूक्रेन द्वारा किए गए झोले हमले के जवाब में किया गया।

एजेंसियों की मदद करना ट्रंप की 'वैधानिक जिम्मेदारी': संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क/एपी।

संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि विश्व निकाय द्वारा संचालित 30 से अधिक पहलों से समर्थन वापस लेने की व्हाइट हाउस की घोषणा के बाद भी अमेरिका की यह वैधानिक जिम्मेदारी है कि वह संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों को वह धन दे जिसका वादा किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेर्रेस ने कहा कि उन्हें विश्व निकाय से संबंधित 31 एजेंसियों से अमेरिका को बाहर निकालने संबंधी राष्ट्रपति जोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर खेद है। दरअसल ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र के कई निकायों और भारत-फ्रांस नीत अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) समेत 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका को बाहर निकालने का फैसला किया है।

10-01-2026
सूर्योदय 5:58 बजे

11-01-2026
सूर्यास्त 6:34 बजे

BSE 83,576.24
(-604.72)

NSE 25,683.30
(-193.55)

सोना 14,344 रु.
(24 रु.) प्रति ग्राम

चांदी 268,000 रु.
प्रति किलो

निशान मंडेला

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी दैनिक
epaper.dakshinbharat.com



कैलाश मण्डेला, मो. 9828233434

आफतकाल का जाल

यह चुनाव का वर्ष बन रहा, सभी दलों का आफतकाल। है विपक्ष आपातकाल में, कोस रहे हो कर बेहाल। येनकेन कैसे भी हो बस, गल जाए मतलब की दाल। फँस जाए वोटर मछली सा, फँक रहे बातों के जाल।।

शाह ने एनएसजी के राष्ट्रीय आईईडी डेटा मंच की शुरुआत की

आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा एनआईडीएमएस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



गुरुग्राम/भाषा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक राष्ट्रीय डिजिटल आईईडी डेटा प्रबंधन मंच की शुरुआत की, जो "आतंकवाद के खिलाफ अगली पीढ़ी के सुरक्षा कवच" के रूप में कार्य करेगा और देश में होने वाले सभी प्रकार के बम विस्फोटों के खिलाफ एक व्यापक प्रतिरोधक होगा।

राष्ट्रीय आईईडी डेटा प्रबंधन प्रणाली (एनआईडीएमएस) को संघीय आतंकवाद-रोधी कमांडो बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) द्वारा गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-दिल्ली, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की

मदद से विकसित किया गया है। यह सभी प्रकार के बम विस्फोटों का "सटीक" अध्ययन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग उपकरणों से लैस है।

देश में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) विस्फोटों को आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में "सबसे चुनौतीपूर्ण" खतरों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इन वर्षों में आईईडी विस्फोट में हजारों नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये एक लिंक के

माध्यम से इस मंच का उद्घाटन किया। यह केंद्र मानेसर स्थित राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) छावनी में स्थित है।

मंत्री ने कहा कि एनआईडीएमएस आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ एक "बाल" और "राष्ट्रीय संपत्ति" के रूप में काम करेगा क्योंकि यह पुलिस, विभिन्न जांच एजेंसियों, राज्य आतंकवाद-रोधी दस्तों, एनआईए जैसी संघीय एजेंसियों तथा केंद्रीय बलों को विभिन्न प्रकार के बम विस्फोटों के तौर-तरीके और कार्यप्रणाली का विश्लेषण करने के लिए "व्यापक" डेटा प्रदान करेगा।

नदी जल को लेकर आंध्र और तेलंगाना के बीच विवाद की जरूरत नहीं : नायडू

रायचूरम (आंध्र प्रदेश)/भाषा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को कहा कि समुद्र में व्यर्थ बह जाने वाले नदी जल को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद की कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वी गोदावरी जिले में एक ग्रामीण बैठक को संबोधित करते हुए नायडू ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जल उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जानबूझकर विवाद पैदा कर रहे हैं। किसानों को नये "पट्टावार पासबुक" (भूमि दस्तावेज) विलरित करते हुए उन्होंने कहा, समुद्र में बेकार बह जाने वाले पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद की क्या जरूरत है? कुछ लोगों को पानी नहीं, बल्कि विवाद चाहिए। किसी का नाम लिए बिना नायडू ने वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के नाम पर विवाद भड़काने की कोशिश की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य कृष्णा नदी पर स्थित मीशेलम जलाशय के जल का उपयोग कर सूखाग्रस्त रायलसीमा क्षेत्र में सिंचाई और पानी की उपलब्धता में सुधार करना है।



ऊंट महोत्सव



राजस्थान के बीकानेर में शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव के पहले दिन पारंपरिक वेशभूषा और आकर्षक सिरपोश में सजे लोक कलाकार तस्वीर के लिए पोज देते हुए।

शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है : भारत

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने शुक्रवार को शक्सगाम घाटी में चीन की अवसररचना विकास परियोजनाओं की आलोचना की और कहा कि चूंकि यह भारतीय क्षेत्र है, इसलिए वह अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से शक्सगाम घाटी स्थित 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को चीन को सौंप दिया था, जो उन क्षेत्रों का हिस्सा था जिन पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।



विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान 'सीमा समझौते' को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार यह कहते आए हैं कि यह समझौता अवैध और अमान्य है।" उन्होंने अपनी साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हम तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी मान्यता नहीं देते हैं, जो भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर पाकिस्तान का जबरन और अवैध कब्जा है।"

स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करना सामूहिक जिम्मेदारी : प्रधान

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने स्कूलों को समाज में जीवंत संस्थाओं के रूप में पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि पढ़ाई में पिछड़ेपन को दुरुस्त करना, विद्यार्थियों के स्कूल छोड़ने, प्रवृत्ति में कमी लाना तथा हर बच्चे में आलोचनात्मक सोच विकसित करना सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधान ने यहां केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा योजना से जुड़े हितधारकों के साथ आयोजित



परामर्श बैठक में ये बातें कहीं। उन्होंने समुदाय की भूमिका पर विस्तार से बात करते हुए कहा कि व्यवस्था और वेतन की जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए, लेकिन स्कूलों के मालिकाना और संचालन में पूरे समाज की सहभागिता आवश्यक है। प्रधान ने कहा, "व्यवस्था और वेतन की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, लेकिन स्कूलों के संचालन की जिम्मेदारी समाज की

होनी चाहिए। जैसे-जैसे हम समग्र शिक्षा के नये ढांचे की ओर बढ़ रहे हैं, हमें मिलकर यह सोचना होगा कि इसे कैसे संभव बनाया जाए और स्कूलों को समाज से जुड़ी जीवंत संस्थाओं के रूप में फिर से स्थापित किया जाए।" केंद्रीय मंत्री ने स्कूलों की शिक्षा के कई पहलुओं में सार्थक बदलाव की आवश्यकता पर जोर दिया, जिनमें शैक्षणिक उपलब्धियों में सुधार, पोषण स्तर को मजबूत करना, परीक्षा का बोझ कम करना, अधिगम प्रक्रियाओं को सरल बनाना, कक्षा 12 तक शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना, स्कूलों का समग्र विकास करना तथा तकनीक और डिजिटलीकरण का प्रभावी उपयोग शामिल है।

हिमाचल के सिरमौर में बस के खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नाहन/भाषा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में शुक्रवार दोपहर एक निजी बस के 500 फुट गहरी खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई और लगभग 52 अन्य यात्री घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई, जब शिमला से राजगढ़ होते हुए कुपवी जा रही बस हरिपुरधारा गांव के पास सड़क से फिसलकर खाई में जा गिरी और पलट गई।



बस में 39 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने घटना के प्रति शोक व्यक्त किया और कहा, मैं इस दुर्घटना में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक

संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। मैं घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त

करते हुए मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर एक पोस्टर में कहा, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस दुर्घटना में हुई जानमाल की हानि अत्यंत दुखद है। अपनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना है। मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 63 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

रायपुर/भाषा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 63 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया है तथा उनमें 36 पर 1.19 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में जारी नक्सल विरोधी मोर्चे पर सुरक्षाबलों को शुक्रवार को महत्वपूर्ण सफलता मिली जब पूना मारोम (पुनर्वास से पुनर्जीवन) अभियान से प्रभावित होकर 36 ईनामी समेत 63 माओवादी समाज की



मुख्यधारा में शामिल हो गए। उन्होंने बताया कि आज आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 18 महिलाएं हैं। अधिकारियों का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादी दक्षिण बस्तर, पश्चिम बस्तर, अबुझमाड़ और उडीसा में सक्रिय थे। उनमें 36 माओवादियों पर एक करोड़,

19 लाख, 50 हजार का इनाम घोषित था। अधिकारियों के अनुसार माओवादियों के आत्मसमर्पण करने के समय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के उप महानिरीक्षक राकेश चौधरी, दंतेवाड़ा जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव राय और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

जमीन के बदले नौकरी घोटाला:

लालू यादव, अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



नई दिल्ली/भाषा। राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख एवं पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ कथित जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरोप तय करने का शुक्रवार को आदेश दिया।

यादव ने रेल मंत्रालय को अपनी निजी जागीर की तरह में इस्तेमाल किया ताकि वह एक आपराधिक गतिविधि को अंजाम दे सकें।

इस्तेमाल करके यादव परिवार ने रेलवे अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों की मिलीभगत से जमीन हासिल की। आदेश के मुख्य हिस्से को मौखिक रूप से सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई की अंतिम रिपोर्ट से गंभीर संदेह के आधार पर एक व्यापक साजिश का खुलासा

होता है। उन्होंने लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों समेत आरोपियों द्वारा बरी किए जाने की याचिका को भी "अनुचित" बताते हुए खारिज कर दिया और इस बात पर जोर दिया कि पूर्व रेल मंत्री और अन्य लोग "भूमि हड़पने के लिए एक संगठित आपराधिक समूह की तरह काम कर रहे थे।"

रिहसल



शुक्रवार को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहसल के दौरान भारतीय वायुसेना का दल उत्साह के साथ जयकारे लगाते हुए।





बीकानेर में तीन दिन का अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव शुरू

जयपुर। राजस्थान के बीकानेर में शुक्रवार को तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव शुरू हुआ जिसमें पहले दिन स्थापत्य कला, व्यंजन और लोक कलाओं के विविध आकर्षक रंग देखने को मिले। नौ से 11 जनवरी तक चलने वाले इस उत्सव का आगाज 'हेरिटेज वॉक' के साथ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। मेघवाल ने कहा कि तीन दिवसीय ऊंट उत्सव से बीकानेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत सरकार के कुछ संस्थानों से लोक कलाकारों को जोड़ जाएगा।

उन्होंने कहा कि एक हजार हवेलियों वाले बीकानेर में हवेलियों को कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। 'हेरिटेज वॉक' में बीकानेर की स्थापत्य कला, व्यंजन और लोक कलाओं के विविध आकर्षक रंग देखने को मिले। इस अवसर पर देशी-विदेशी सैलानी, स्थानीय निवासी, जनप्रतिनिधि तथा प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी बीकानेरी रंगों में सराबोर नजर आए। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने सूर्य नमस्कार की बारह मुद्राओं पर आधारित मूर्तिकला का लोकार्पण किया।



राज्यपाल ने पूर्व मंत्री जोशी के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दी

जयपुर। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है। लोकभवन के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक बयान के अनुसार बागडे ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पूर्व मंत्री महेश जोशी के विरुद्ध धनशोधन रोकथाम अधिनियम 2002 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है। बयान के मुताबिक बागडे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते महेश जोशी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने राजस्थान में जल जीवन मिशन (जेजेएम) से जुड़े कथित धनशोधन मामले में पूछताछ के बाद जोशी को 24 अप्रैल, 2025 को गिरफ्तार किया था। जोशी की गिरफ्तारी राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा आठ अगस्त 2023 को दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत की गई थी। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

पीएचडी विभाग का अभियंता रिश्वत में आईफोन लेते हुए पकड़ा गया

जयपुर। राजस्थान के झालावाड़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचडी) के एक अधीक्षण अभियंता को कथित तौर पर रिश्वत के रूप में आईफोन लेते हुए गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ब्यूरो के अनुसार अधीक्षण अभियंता विष्णुचंद गोयल को परिवारी से बतौर रिश्वत आईफोन लेते हुए गिरफ्तार किया गया। फोन की कीमत 84 हजार रुपए बताई गई है। ब्यूरो का कहना है कि परिवारी ने शिकायत की थी कि पीएचडी में हैंडपंप की मरम्मत और पाइपलाइन रिसाव की मरम्मत आदि का काम चल रहा है। विभाग के कर्मों इसमें पंजीकरण करवाने की एजेंज में उससे पचीस हजार रुपये ले चुके हैं तथा वे कामकाज में कर्मियों निकालकर उसे और उसके साझेदार को काम से हटाने की धमकी देते हैं। परिवारी का आरोप है कि वह जब अधीक्षण अभियंता से मिला तो उन्होंने उसका बकाया बिल पास करने तथा परेशान नहीं करने की एजेंज में 'आईफोन 16 प्रो' मांगा। ब्यूरो ने कहा कि शिकायत को सत्यापित करने के बाद परिवारी ने शुक्रवार को अन्य मंडल का आईफोन आरोपी को दिया। एनसीबी टीम ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मामले में आगे जांच की जा रही है।

अनेक इलाके शीतलहर की चपेट में, कई जगह बारिश

जयपुर। राजस्थान के अनेक इलाकों में शीतलहर का दौर जारी है और बीते चौबीस घंटे में कई जगह हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने शुक्रवार सुबह यह जानकारी दी। विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गयी। साथ ही राज्य के कुछ भागों में घना से अति घना कोहरा, शीत लहर व अति शीत दिन दर्ज किए गए। इस दौरान सर्वाधिक बारिश झुंझुनू में 5.0 मिलीमीटर हुई। इस दौरान अधिकतम तापमान जवाई बांध (पाली) में 24.4 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान जौसलमेर में 4.6 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में आगामी एक सप्ताह मौसम शुक्र रहने तथा आगामी 1-2 दिन राज्य के कुछ भागों में सुबह के समय अति घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अनेक जगह शीतलहर जारी रहेगी।

जोधपुर कोर्ट परिसर में वकीलों और महिला पुलिस अधिकारी के बीच तनाव

जोधपुर। शहर के कोर्ट परिसर में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब एक वकील की कार से महिला पुलिस अधिकारी की गाड़ी टकरा गई। घटना के बाद आरोप है कि महिला पुलिस अधिकारी ने वकील के साथ दुर्व्यवहार किया। घटना के तुरंत बाद महिला पुलिस अधिकारी सीधे वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट संख्या-8 की अदालत परिसर में पहुंच गई। इस बीच आक्रोशित वकीलों ने अधिकारी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की, लेकिन अधिकारी ने माफी देने से इनकार कर दिया। माफी न मिलने के कारण वकीलों ने कोर्ट परिसर में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

शाह के जोधपुर आगमन से पहले प्रशासन अलर्ट

जोधपुर। देश के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के आज शाम जोधपुर आगमन से पहले प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आईं। वीवीआईपी विजिट को लेकर एयरपोर्ट से बीएसएफ कार्यालय मंडोर तक काफिला मार्ग (कारोटे) का व्यापक सुरक्षा रिवर्सल किया गया। रिवर्सल के दौरान पुलिस, बीएसएफ, खुफिया एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इस अभ्यास में काफिले की गति, सुरक्षा घेरे, ट्रैफिक डायवर्जन, आपातकालीन व्यवस्थाओं और संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित प्रतिक्रिया का रियल-टाइम परीक्षण किया गया। एयरपोर्ट से मंडोर स्थित बीएसएफ कार्यालय तक पूरे मार्ग पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग पॉइंट लगाए गए, वहीं झूना, सीसीटीवी कैमरों और सटीक वर्दी में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार निगरानी रखी गई। यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी लागू किया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह रिवर्सल केंद्रीय गृहमंत्री की सुरक्षा और उनके कार्यक्रम के निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।



विगत दो वर्षों में बुनियादी ढांचे में हुआ बड़ा सुधार गांव-ढाणी तक मिल रहा गुणवत्तापूर्ण इलाज : भजनलाल शर्मा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और संवेदना से जुड़ा क्षेत्र है। विगत दो वर्षों में राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आगे भी स्वास्थ्य के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है। इससे गांव-ढाणी तक प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क उपचार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट पूर्व संवाद का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों से एक ऐसा बजट बने, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और राजस्थान स्वास्थ्य में सिरमौर बने। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार 'पहला सुख निरोगी काया' अर्थात् स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा सुख होता है। इसी

अवधारणा के साथ प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 लाख मरीजों को 7 हजार 300 करोड़ रुपये का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया गया है। इसी तरह, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है। इससे गांव-ढाणी तक प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क उपचार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट पूर्व संवाद का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों से एक ऐसा बजट बने, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और राजस्थान स्वास्थ्य में सिरमौर बने। शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार 'पहला सुख निरोगी काया' अर्थात् स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा सुख होता है। इसी

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है। हर रोगी को संवेदनशीलता के साथ अच्छा उपचार मिले और जीवन रक्षा का उद्देश्य फलीभूत हो। यही इस क्षेत्र की महानता है। चिकित्सकों एवं इस क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को चाहिए कि वे अपने दायित्वों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाएं। राज्य सरकार ऐसे सेवाभावी कर्मियों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगी। लेकिन जनता के पैसे का दुरुपयोग

करने वाले एवं स्वास्थ्य योजनाओं में अनियमितता करने वाले कर्मिकों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि प्रदेश को प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 15 नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माणधीन हैं। साथ ही, भीलवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा एवं बूंदी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिले। इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निचले स्तर तक चिकित्सा सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विगत दो वर्षों में 7 उप जिला अस्पताल, 2 सेंटेंलाइड अस्पताल, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 14 संस्थानों का जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन तथा 7 नवीन सेंटेंलाइड अस्पतालों की स्थापना की गई है।

स्थायी लोक अदालत का बड़ा आदेश

विद्युत निगम 35 माह से अधिक पुराने बकाया की वसूली नहीं कर सकेगा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। स्थायी लोक अदालत दौसा ने एक अहम फैसले में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को 35 माह से अधिक पुराने बकाया बिलों की वसूली पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मैसर्स शारदा इंडस्ट्रीज एवं अन्य बनाम जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड प्रकरण में पारित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संतोष अग्रवाल ने बताया कि स्थायी लोक अदालत में पूर्णकालिक अध्यक्ष आर.सी. गुप्ता तथा सदस्य अशोक कुमार शर्मा और सुरेश कुमार गोयल द्वारा मामले की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सहायक अभियंता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, बांटीकुई ग्रामीण द्वारा मैसर्स शारदा इंडस्ट्रीज आर.सी. बोटलिंग के विरुद्ध प्रस्तुत बकाया बिलजिसमें ट्रांसफार्मर लॉस, पावर फैक्टर सूरचार्ज, ट्रांसफार्मर किराया एवं सीटी-पीटी रेंट के रूप में कुल 2 लाख 36 हजार 193 रुपये की मांग की गई थीको वसूली योग्य नहीं

माना गया। स्थायी लोक अदालत ने पीडित पक्ष का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि विद्युत वितरण निगम केवल पिछले दो वर्षों की अवधि के बिलों की राशि ही वसूल कर सकता है। इससे अधिक पुराने किसी भी बिल की वसूली नहीं की जा सकती।

सचिव संतोष अग्रवाल ने आमजन से अपील की कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा लोक उपयोगिता से जुड़ी समस्याओं के त्वरित और सुलभ समाधान के लिए फरवरी माह के प्रथम सप्ताह तक एक विशेष अभियान चलया जा रहा है। इस अभियान के तहत बिजली, पानी, परिवहन, बैंकिंग एवं बीमा, नगर निकाय, स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, आवास एवं भू-सम्पदा सेवाएं, एलपीजी सेवा सहित अन्य जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित शिकायतें निर्धारित प्रारूप या साधारण हस्तलिखित आवेदन के माध्यम से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समर्पित मोबाइल नंबर 9119365734 पर सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि अभियान के

अंतर्गत प्राप्त शिकायतों पर प्राधिकरण द्वारा शिकायतकर्ता से संपर्क कर स्थायी लोक अदालत दौसा में निःशुल्क पैरवी के लिए लोअर एड डिफेंस कार्सिल की नियुक्ति भी की जाएगी।

सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत

जयपुर। राजस्थान के अजमेर जिले में बृहस्पतिवार रात सड़क हादसे में दो भाइयों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार पीसंगन थानाक्षेत्र के लेसावा गांव में बजर से भरा डंपर असंतुलित होकर मोटरसाइकिल पर गिर गया। इस हादसे में गोविंदगढ़ के रहने वाले अभिषेक सेन (25) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके छोटे भाई आशीष सेन (23) गंभीर रूप से घायल हो गए और देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया जबकि उसके मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने यह भी बताया कि डंपर को जव्त कर लिया गया है।



केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल पॉलिसी की सराहना की

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने असम के गुवाहटी में राष्ट्रीय कपड़ा मंत्रियों के सम्मेलन में राजस्थान सरकार की टेक्सटाइल पॉलिसी को आदर्श बताते हुए सभी राज्यों को इसी प्रकार अपने टेक्सटाइल उद्योग के विकास और निवेश के लिए रोडमैप तैयार करने की सलाह दी है। कार्यक्रम में उनको राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025 की प्रति दी गई, इसे गौर से पढ़कर इसमें दिलचस्पी दिखाई, सम्बन्धित लोगों से फीडबैक लिया और इस नीति की सराहना की। इस दो-दिवसीय सम्मेलन में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कपड़ा मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी कपड़ा क्षेत्र के भविष्य के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए जुटे हैं। इसमें राजस्थान सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के. विश्वोई के नेतृत्व में शामिल हुआ है, जिसमें वरिष्ठ अतिरिक्त आयुक्त एसएस शाह सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। सम्मेलन में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय ने राजस्थान सहित 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापनों (एसओयू) पर हस्ताक्षर करके साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की

दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। वस्त्र मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन वस्त्र केंद्रित अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी, योजना और स्टार्ट-अप (टेक्स-आरएएमपीएस) योजना का हिस्सा हैं। केंद्र सरकार की यह योजना वस्त्र संबंधी सांख्यिकीय उपायों और अनुसंधान की व्यापकता, गुणवत्ता, समयबद्धता और विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए बनाई गई है। इन समझौता ज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वस्त्र संबंधी डेटा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए एक मजबूत परिचालन ढांचा तैयार किया गया है। टेक्स-आरएएमपीएस योजना के तहत, यह पहल क्लस्टर और जिला स्तर पर सीधे प्रयास केंद्रित करके हथकरघा, हस्तशिल्प, परिधान, तकनीकी वस्त्र आदि सहित प्रमुख क्षेत्रों के लिए एकीकृत योजना को बढ़ावा देती है। इन संरचनात्मक सुधारों में सहयोग देने के लिए वस्त्र मंत्रालय प्रत्येक राज्य को प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान प्रदान कर रहा है। इसमें प्रत्येक जिले के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये का अतिरिक्त अनुदान शामिल है, जिसका वितरण विशिष्ट जिला कार्य योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के आधार पर किया जाएगा।

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने कहा कि राजस्थान के लिए यह गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर उसकी नीतियों की सराहना की जा रही है और अन्य राज्यों को इस तरह की नीतियां बनाने का सुझाव दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पॉलिसी-2025 सहित कई नई नीतियां लागू की गई हैं, जिनका भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। इस पॉलिसी में नियतकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार गारमेंट मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को भी शामिल किया गया है। प्राकृतिक एवं कृत्रिम फाइबर उत्पादन को बढ़ाने से लेकर तकनीकी टेक्सटाइल्स और वस्त्र विनिर्माण, हैंडलूम, ऊन प्रसंस्करण, चमड़े के उत्पाद, फुटवियर जैसे संबंधित क्षेत्र भी इस नीति का हिस्सा हैं। इस नीति के तहत वस्त्र और परिधान क्षेत्र के उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 10 वर्षों तक 80 करोड़ रुपये वार्षिक तक का एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, भूमि/भवन क्रय या लीज पर स्टॉप ज्यूटी व पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, बिजली उपभोग पर 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिसिटी ज्यूटी छूट का प्रावधान किया गया है।



राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध : मुख्य सचिव

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में सरकार द्वारा समयबद्ध एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करते हुए सरकारी क्षेत्र में 4 लाख तथा निजी क्षेत्र में 6 लाख सहित कुल 10 लाख रोजगार सृजित करने के संकल्प पर निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मुख्य सचिव शुक्रवार को शासन सचिवालय में उद्योगआईटीआई के बेहतर समन्वय, संस्थान प्रबंधन समितियों एवं आईटीआई के सुदृढीकरण के सम्बन्ध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने

अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के अधिक से अधिक आईटीआई को उद्योगों से जोड़ा जाए, जिससे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ उद्योगों की व्यावहारिक समझ भी प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों के नवाचारों एवं श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को अपनया जाए तथा प्रदेश के आईटीआई को 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के रूप में विकसित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएं। इस अवसर पर उन्होंने झालावाड़ आईटीआई को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई देते हुए अन्य आईटीआई को भी इसी प्रकार कार्य कर शिक्षा के स्तर में निरंतर सुधार लाने के निर्देश दिए।

बैठक में मुख्य सचिव ने संस्थान प्रबंधन समितियों को और अधिक सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

माध्यम से जुड़े आईटीआई अधिकारियों को अपने-अपने संस्थानों में संचालित ट्रेड्स तथा प्रस्तावित नए ट्रेड्स की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी आईटीआई के दीक्षात समारोह की जानकारी साझा कर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी प्रसारित करने के निर्देश दिए।

बैठक में संदीप वर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग, भवानी सिंह देथा, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास, पी. रमेश शासन सचिव श्रम विभाग, श्रीमती टीना सोनी शासन सचिव वित्त (व्यय) विभाग, रिशव मंडल, आयुक्त कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों के आईटीआई प्राचार्य एवं अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।

सेना दिवस समारोह से पहले जयपुर में परेड कमांडर की परेड

जयपुर। यहां महल रोड पर शुक्रवार को परेड कमांडर की परेड हुई जिसमें भारतीय सेना की विभिन्न बटालियन, टैंक, मिसाइल, जून और आधुनिक हथियार प्रणालियों का मार्च शामिल था। यहां 15 जनवरी को होने वाले सेना दिवस समारोह से पहले यह कार्यक्रम एक जनवरी से शुरू हुए कई अभ्यास के तहत आयोजित किया गया। इन कार्यक्रमों के तहत अब 11 जनवरी को चीफ ऑफ स्टॉफ की परेड, 13 जनवरी को आर्मी कमांडर की परेड और 14 जनवरी को सेना दिवस परेड का मुख्य कार्यक्रम होगा।

पहली बार यह परेड सैन्य क्षेत्र के बाहर आयोजित की जा रही हैं। शहर में कड़ाके की सर्दी के बावजूद बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आए। कार्यक्रम की शुरुआत आर्मी बैंड के प्रदर्शन से हुई, जिसके बाद वीरता पुरस्कार विजेता अधिकारियों ने परेड कमांडर को औपचारिक सलामी दी। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित सैन्य अधिकारियों ने परेड की अगुवाई की। उनके पीछे आर्मी बैंड और घुड़सवार इकाई मार्च कर रही थी। सेना के विशेष धान वस्त्रे और 'रोबोटिक डॉग' ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया।

सुविचार

हमेशा याद रखना अगर एक दरवाजा बंद होता है तो परमात्मा दस दरवाजे और खोल देता है

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

हल्का बस्ता, खुशहाल बचपन

केरल सरकार स्कूली बस्ते का बोझ कम करने और ‘बैकबेंचर्स’ की धारणा को बदलने के लिए जो पहल कर रही है, वह अनूठी है। इसकी बहुत जरूरत है। विद्यार्थियों के हित के लिए ऐसे कदम उठाने के बारे में कम ही सरकारें सोचती हैं। भारत की शिक्षा पद्धति और स्कूलों के माहौल में सुधार लाने के लिए बड़े स्तर पर कोशिशें होनी चाहिए। इन दोनों बिंदुओं को बच्चों के नजरिए से देखना होगा। क्या वजह है कि कई बच्चे स्कूल जाते समय रोते हैं? वे छुट्टी की घंटी बजते ही ऐसे क्यों भागते हैं, जैसे किसी कैदखाने से निकलकर भागे हों? बच्चे अपने खिलौनों से बहुत प्यार करते हैं। वे उन्हें संभालकर रखते हैं। वे स्कूली किताबों से क्यों दूर रहना चाहते हैं? जवाब है— पढ़ाई अरुचिकर है। अगर स्कूली किताबें शिक्षक पढ़ेंगे तो वे उन्हें बहुत आसान लगेंगी, क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर ऊंचा होता है। जब बच्चे उन्हें पढ़ेंगे तो वे उन्हें मुश्किल लगेंगी, क्योंकि लेखकों ने बच्चों की तरह सोचा ही नहीं था! अक्सर लोग सोशल मीडिया पर अपने स्कूली दिनों के अनुभव साझा करते हैं। वे अपने स्कूल से जुड़ीं मधुर यादों को संजोकर रखते हैं। उनसे पूछा जाए, ‘आपने जो किताबें पढ़ीं, रात-रातभर जागकर अगले दिन परीक्षाएं दीं, क्या एक बार फिर उन्हीं घटनाओं का सामना करना चाहेंगे?’ तो ज्यादातर लोग तौबा कर लेंगे। स्कूलों का माहौल ऐसा होना चाहिए कि बच्चा रोने-धोने के बजाय बहुत खुश होकर वहां जाना चाहे। उसे स्कूली किताबें रुचिकर लगे। उसका बचपन खुशहाल होना चाहिए। भारत की आजादी के बाद सरकार को इन बातों की ओर तुरंत ध्यान देना चाहिए था।

फिनलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, जापान और जर्मनी जैसे देशों ने प्रारंभिक शिक्षा में बहुत सुधार किए हैं। वहां बच्चों पर अकादमिक दबाव कम डाला जाता है। उन्हें आत्मविश्वासी और अनुशासित बनाने पर जोर दिया जाता है। नीदरलैंड में हर बच्चे की सीखने की गति का सम्मान किया जाता है। जापान में सामाजिक व्यवहार पर खास ध्यान दिया जाता है। वहां बच्चों को शारीरिक दंड देने, सबके सामने अपमानित करने की घटनाएं नहीं होतीं, जबकि हमारे देश में इन घटनाओं के वीडियो वायरल होते रहते हैं। हाल के वर्षों में कई शिक्षकों पर अपने छात्रों को बेदर्दी से पीटने, घायल करने और जान लेने तक के आरोप लगे हैं। कुछ शिक्षक अपने घर-परिवार का गुस्सा स्कूल में बच्चों पर उतारते हैं। वे किसी बच्चे को सबके सामने खरी-खोटी सुनाते हैं या उसकी पिटाई कर देते हैं। कुछ समय बाद वे तो इसे भूल जाते हैं, लेकिन बच्चे ऐसी घटनाओं को जीवनभर नहीं भूल पाते। कुछ बच्चों का स्वभाव बहुत संवेदनशील होता है। वे अपमान बर्दाश्त न कर पाने के कारण गलत कदम उठा लेते हैं। किसी स्कूल में बच्चे लगातार ऐसे माहौल को झेलेंगे तो उनका कितना बौद्धिक और नैतिक विकास होगा? कई शिक्षकों को एक और गलतफहमी है। वे सोचते हैं कि बच्चों के साथ जितनी ज्यादा सख्ती बरतेंगे, वे उतने ही अनुशासित होंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल ही बेबुनियाद है। छड़ी के जोर से जो अनुशासन आता है, वह क्षणिक होता है। क्या वजह है कि जापान स्वच्छता, ईमानदारी, आपसी सहयोग और अनुशासन के मामले में बहुत बेहतर स्थिति में है, जबकि वहां के स्कूलों में ‘ज्यादा सख्ती’ नहीं है? अनुशासन सिखाया जाता है, थोपा नहीं जाता। स्कूलों में अच्छी आदतें सिखाया पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। सिर्फ किताबें रटने से न तो बच्चे का भविष्य उज्ज्वल होता है, न देश को कोई फायदा मिलता है।

ट्वीटर टॉक



वसुधैव कुटुम्बकम् की कालजयी भावना को आत्मसात कर विश्व पटल पर भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक पहचान को गौरव के साथ स्थापित करने वाले समस्त प्रवासी भारतीय भाई-बहनों को प्रवासी भारतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

—ओम बिरला

विकसित राजस्थान 2047 के स्वर्णिम स्वप्न को साकार करने की दिशा में आज मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ऐतिहासिक पहल हुई, जहां चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया गया।

—भजनलाल शर्मा

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी के प्रतीक इस दिवस पर दुनिया भर में बसे सभी भारतीयों का अभिनंदन। आपने अपनी प्रतिभा, कर्मठता और संस्कार से सात समंदर पार भी भारत का गौरव बढ़ाया है। हमें आप पर गर्व है।

—अशोक गहलोत

प्रेरक प्रसंग

वास्तविक सम्राट

न

प्राट अशोक एक दिन अपने साम्राज्य का निरीक्षण करते हुए एक बौद्ध भिक्षु से मिले। भिक्षु के हाथ में केवल एक मिट्टी का कटोरा था। अशोक ने पूछा ‘तुम्हारे पास इतना ही है?’ भिक्षु मुस्कुराया ‘महाराज, इससे अधिक मेरी आवश्यकता नहीं। यह उत्तर अशोक को भीतर तक छू गया। उनके पास असीम सत्ता, सोना और सेनाएं थीं, फिर भी मन अशांत था; जबकि सामने खड़ा व्यक्ति अल्प साधनों में पूर्ण शांत था। उसी क्षण अशोक को बोध हुआ कि विजय बाहरी नहीं, भीतर की होनी चाहिए। उस दिन के बाद उन्होंने शासन का अर्थ बदलावमन नहीं, सेवा; भय नहीं, विश्वास; और अपने इस विचार को जीवन में उतारा, जिसके पास सब कुछ होते हुए भी शांति नहीं, वह निर्धन है; और जो कम में संतुष्ट है, वही वास्तव में सम्राट है।



सामयिक

जांच के घेरे में राजनीति, राजनीति के घेरे में जांच

प्रो. आरके जैन ‘अरिजीत’



ज

ब सत्ता के गलियारों में कानून की दस्तक पड़ती है, तब केवल फाइलें नहीं हिलतीं, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा शुरू हो जाती है। 8 जनवरी 2026 की सुबह कोलकाता ने ठीक ऐसा ही दृश्य देखा, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक सामान्य प्रतीत होने वाली छापेमारी अचानक राजनीति, संविधान और संघीय संतुलन के टकराव का प्रतीक बन गई। कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में जुटी ईडी की टीम जैसे ही विभिन्न ठिकानों पर पहुंची, वैसे ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मोके पर उपस्थित हुईं और कुछ दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाहर ले गईं। मुख्यमंत्री ने इसे पार्टी की गोपनीयता बचाने का कदम बताया, जबकि ईडी ने इसे जांच में बाधा और सबूत हटाने का आरोप लगाया। यही क्षण जांच की वैध सीमाओं से आगे बढ़कर राजनीतिक संघर्ष, संवैधानिक अधिकारों और चुनावी निष्पक्षता पर छिड़ी एक व्यापक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया।

इस कार्रवाई की परिधि केवल कोलकाता तक सीमित नहीं रही, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ शहर में छह और दिल्ली में चार ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी का कहना है कि यह जांच कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़े अवैध धन के हवाला नेटवर्क पर केंद्रित है और पूर्व मामलों की ताकिक कड़ी का हिस्सा है। शुरूआती चरण में जांच शांतिपूर्ण रूप से आगे बढ़ रही थी, किंतु मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बाद चुनावी रणनीति, डिजिटल डेटा और पार्टी गोपनीयता की सुरक्षा का मुद्दा केंद्र में आ गया। यहीं से कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के बीच तनाव स्पष्ट रूप से उभरने लगा।

मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोलकाता स्थित अपने आवास और साल्ट लेक के कार्यालय, दोनों स्थानों पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम पर प्रत्यक्ष नजर रखी। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले की गई इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से प्रेरित बताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि

चुनावी तैयारियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों और रणनीतिक सूचनाओं की जब्ती लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसी चिंता के आधार पर उन्होंने राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया और जनता से संस्थागत अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थकों ने इस कदम को संवैधानिक अधिकारों और चुनावी गोपनीयता की रक्षा का साहसिक उदाहरण माना, जबकि विपक्षी दलों ने इसे जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप और संभावित सबूत नष्ट करने का प्रयास बताया।

प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के हस्तक्षेप को जांच में बाधा करार देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। एजेंसी का दावा है कि छापेमारी पूरी तरह कानूनी है, कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोस साक्ष्यों (हवाला लिंक सहित) पर आधारित है, और मुख्यमंत्री ने जबर्न दस्तावेज व उपकरण हटाए। ईडी का दावा है कि कोयला तस्करी से प्राप्त अवैध धन हवाला के जरिए आई-पैक को टीएमसी के 2022 गोवा चुनाव अभियान के लिए दिया गया था। वहीं, आई-पैक ने भी अदालत में याचिका दायर कर छापों की वैधता और समय पर सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें संकेत देती हैं कि अब इस विवाद की दिशा न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक संतुलन से ही तय होगी। यह प्रक्रिया आने वाले समय में संस्थागत स्वतंत्रता और जवाबदेही, दोनों की निर्णायक परीक्षा बनेगी।

यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर चली आ रही बहस को एक बार फिर तीव्र करता है। आई-पैक जैसी संस्थाएं चुनावी रणनीति, डिजिटल प्रबंधन और जनसंपर्क संचालन में अहम भूमिका निभाती हैं, जिनका सीधा प्रभाव मतदाता व्यवहार पर पड़ता है। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले की गई छापेमारी की टाइमिंग स्वायत्तता और निष्पक्ष प्रतिक्रिया पर प्रश्न खड़े करती है। अन्य राज्यों में सामने आए समान प्रसंग भी यह स्पष्ट करते हैं कि संघीय ढांचे में पारदर्शिता और संवाद अनिवार्य है, ताकि लोकतंत्र की जड़ें हर परिस्थिति में मजबूत और विश्वसनीय बनी रहें।

दोनों पक्षों के तर्कों का संतुलित मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि यदि प्रवर्तन निदेशालय की जांच दोस और विश्वसनीय सबूतों पर आधारित है, तो उसे पूरी तरह वैध माना जाना चाहिए। अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई लोकतांत्रिक शासन की अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही, चुनावी गोपनीयता और समय की संवेदनशीलता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप टीएमसी के लिए राज्य अधिकारों और चुनावी गोपनीयता की रक्षा का प्रयास था, जबकि ईडी और विपक्ष ने इसे सबूतों को जबर्न हटाने और जांच बाधित करने का गंभीर आरोप लगाया, जिसका अंतिम आकलन न्यायिक निर्णय से ही संभव होगा। यही प्रक्रिया संस्थागत भरोसे को सुदृढ़ करेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर दिशा

प्रदान करेगी।

इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। समर्थक इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का साहसिक उदाहरण मानते हैं, जबकि आलोचक इसे जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। यह मतभेद स्वयं लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है, जहां सत्ता और संस्थाओं के निर्णयों पर सवाल उठाए जाते हैं। जनभागीदारी और जागरूक बहस किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान होती है, जो इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई है और वर्तमान परिदृश्य में भविष्य के राजनीतिक आचरण को दिशा देने की क्षमता रखती है।

यह विवाद भारत के संघीय ढांचे और संस्थागत संतुलन को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों के बीच स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाओं का निर्धारण आवश्यक है।

टीएमसी ने विरोध को गोपनीयता और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा बताया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे जांच बाधित करने का प्रयास कहा। अब सभी की निगाहें अदालत के निर्णय पर टिकी हैं, जो न्याय, पारदर्शिता और भरोसे की पुनर्स्थापना करेगा। जनता का विश्वास, निष्पक्ष प्रक्रिया और स्वतंत्र संस्थाएं ही इस पूरी प्रक्रिया की अंतिम कसौटी होंगी, जिससे लोकतांत्रिक भारत की आधारशिला आने वाले वर्षों के लिए और अधिक मजबूत तथा प्रासंगिक बनेगी। कोलकाता में टीएमसी द्वारा आयोजित प्रस्तावित पदयात्रा (जादवपुर से हाजर) हालिया विवाद पर पार्टी का सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन है। टीएमसी इसे संस्थागत अधिकारों और चुनावी निष्पक्षता की रक्षा का प्रतीक मानती है और दावा करती है कि चुनाव से पहले की गई जांच लोकतंत्र और संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। वहीं विपक्षी दल इसे जांच से ध्यान भटकाने और राजनीतिक नाटक के रूप में देख रहे हैं। इस कारण रैली को शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाए रखना आवश्यक है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। अंततः विवाद का अंतिम निर्णय अदालत और जांच एजेंसियों के माध्यम से ही स्पष्ट होगा।

विश्व हिंदी दिवस पर विशेष

विश्व संवाद की नई धुरी बनती हिन्दी

माना जाना चाहिए कि उसके बाद के करीब एक दशक में हिन्दी बोलने वालों की संख्या में कई करोड़ लोगों की बढ़ोतरी अवश्य हुई होगी।

भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और उस दौरान हमारे यहां की भाषाओं पर भी अंग्रेजी दासता का बुरा प्रभाव पड़ा। इसी कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हिन्दी को ‘जनमानस की भाषा’ बताते हुए वर्ष 1918 में आयोजित ‘हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ में इसे भारत की राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। सही मायने में तभी से हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के प्रयास शुरू हो गए थे और गर्व का विषय यह है कि अब सैकड़ों देशों में हिन्दी का प्रयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अगर भारतीय परिवेश में हिन्दी के प्रचलन को लेकर बात की जाए तो यह चिंता की बात है कि भारतीय समाज में बहुत से लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि हिन्दी बोलने वालों को वे पिछड़ा और अंग्रेजी में अपनी बात कहने वालों को आधुनिक का दर्जा देते हैं। हिन्दी का करीब 1.2 लाख शब्दों का समृद्ध भाषा कोष होने के बावजूद अधिकांश लोग हिन्दी लिखते और बोलते समय अंग्रेजी भाषा के शब्दों का दिल खोलकर इस्तेमाल करते हैं।

ऐसे में विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को हिन्दी भाषा के विकास, उसके व्यापक उपयोग के लाभ तथा उपेक्षा के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया जाए। हिन्दी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक विरासत और राष्ट्रीय आत्मसम्मान की संवाहक है। जब हम अपनी ही भाषा के प्रयोग से संकोच करते हैं तो अनजाने में अपनी पहचान को भी कमजोर करते हैं।

हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग न केवल भाषा को समृद्ध बनाता है बल्कि समाज में सहजता, समानता और भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करता है। लोगों को यह समझाया जाना चाहिए कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और उसका सम्मान व प्रचार-प्रसार करना केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जब तक हम स्वयं अपने दैनिक जीवन, शिक्षा, प्रशासन, तकनीक और डिजिटल मंचों पर हिन्दी को अपनाने का साहस नहीं करेंगे, तब तक इसके विकास की अपेक्षा अधूरी ही रहेगी। साथ ही यह अहसास कराना भी जरूरी है कि भले ही वैश्विक स्तर पर अंग्रेजी का प्रभाव लंबे समय से बना हुआ है परन्तु हिन्दी आज किसी भी दृष्टि से पीछे नहीं है। इंटरनेट, तकनीक, शिक्षा, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संवाद के क्षेत्र में हिन्दी की स्वीकार्यता तेजी से बढ़ रही है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम भाषायी हीनभावना से बाहर निकलकर हिन्दी को गर्व के साथ अपनाने और उसे विश्व मंच पर उसका उचित स्थान दिलाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।

समृद्ध तथा जन-जन की भाषा बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

तकनीकी रूप से हिन्दी को और ज्यादा उन्नत, समृद्ध तथा आसान बनाने के लिए अब कई सॉफ्टवेयर भी हिन्दी के लिए बन रहे हैं। यह हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी की ताकत ही कही जाएगी कि इसके इतने ज्यादा उपयोगकर्ताओं के कारण ही अब भारत में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हिन्दी का भी उपयोग करने लगी हैं। हिन्दी की बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए भारत में ई-कॉमर्स साइटों भी ज्यादा से ज्यादा

ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए हिन्दी में ही अपनी एप’ लेकर आ रही हैं। हिन्दी इस समय देश की सबसे तेजी से बढ़ती भाषा है। अगर 2011 की जनगणना के आंकड़े देखें तो 2001 से 2011 के बीच हिन्दी बोलने वालों की संख्या में हमारे देश में करीब 10 करोड़ लोगों की बढ़ोतरी हुई। वर्ष 2001 में जहां 41.03 फीसदी लोगों ने हिन्दी को अपनी मातृभाषा बताया था, वहीं 2011 में ऐसे लोगों की संख्या करीब 42 करोड़ के साथ 43.63 फीसदी दर्ज की गई और जिस प्रकार हिन्दी का चलन लगातार बढ़ रहा है,

हिन्दी का अधिकाधिक उपयोग न केवल भाषा को समृद्ध बनाता है बल्कि समाज में सहजता, समानता और भावनात्मक जुड़ाव को भी मजबूत करता है। लोगों को यह समझाया जाना चाहिए कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और उसका सम्मान व प्रचार-प्रसार करना केवल सरकारी दायित्व नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। जब तक हम स्वयं अपने दैनिक जीवन, शिक्षा, प्रशासन, तकनीक और डिजिटल मंचों पर हिन्दी को अपनाने का साहस नहीं करेंगे, तब तक इसके विकास की अपेक्षा अधूरी ही रहेगी।

